सजग साधना, सविनय सेवा...गायब है मेवा

रियायतें देकर सामाजिक दायित्व निभा रहा परिवहन निगम घाटे में पहुंचा

प्रकाश भारद्वाज ● शिमला

जागरण विशेष

- निगम प्रबंधन चाहता है रियायतों पर होने वाले खर्च का एकमुश्त भुगतान
- सरकार समय पर ग्रांट न दे तो निगम का चलना संभव नहीं

'सजग साधना, सविनय सेवा' की टैगलाइन के साथ सामाजिक दायित्व निभा रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) से लाभ का मेवा गायब है। परिवहन निगम की बस में बैठते ही सामने इस स्लोगन के साथ लोगों का स्वागत करने वाला यह विभाग घाटे से नहीं उबर पाया है। परिवहन निगम 27 श्रेणियों को रियायती या निश्शुल्क यात्रा सुविधा दे रहा है, लेकिन यह मददगार अब हाथ फैलाने को मजबूर है।

रियायतों पर वर्ष 2020-21 में 433.83 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। प्रति वर्ष यह खर्च बढ़ता चला जाता है। इस कारण निगम 1400 करोड़ रुपये के घाटे में पहुंच चुका है।

चालकों, परिचालकों व पेंशनर्स को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान करना भी मुश्किल हो गया है। हालत यह कि प्रदेश सरकार समय पर ग्रांट जारी न करे तो निगम का चलना संभव नहीं। अब निगम प्रबंधन चाहता है कि रियायतों पर होने वाले खर्च का सरकार एकमुश्त भुगतान करे।

मासिक आय 67 करोड़ खर्च 135 करोड़ रुपये

परिवहन निगम की मासिक आय 67 करोड़ और खर्च 135 करोड़ रुपये है। कर्मचारियों के वेतन पर मासिक 46 करोड़ और पेंशन पर 23 करोड़ रुपये का खर्च आता है। बसों में डीजल डालने का मासिक खर्च 45 करोड़ रुपये रहता है। सामान्य तौर पर तेल का दैनिक खर्च एक करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपये होता है।

परिवहन निगम सामाजिक सरोकार के दृष्टिगत रियायत पर सुविधा उपलब्ध करवाता है। चाहे स्कूली बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने की जिम्मेदारी हो या महिलाओं और दिव्यांगजनों को रियायती सुविधा देने की, निगम इसे पूरी निष्ठा से निभा रहा है। निगम को वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार से 307 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ है, इसके अतिरिक्त पूंजीगत निवेश के लिए 51 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इससे परिवहन निगम को चलाने में मदद मिलती है, लेकिन घाटा पूरा नहीं होता।

इन श्रेणियों को मिल रही रियायत

श्रेणी	वार्षिक खर्च
सरकारी स्कूली छात्र	197.64 करोड़
कालेज व संस्थागत छात्र	8.59 करोड़
निजी स्कूली छात्र	1.65 करोड़
सरकारी कर्मचारी	6.96 करोड़
पुलिस	37.71 करोड़
स्वतंत्रता सेनानी	55 लाख
प्रेस	89 लाख
शौर्य पुरस्कार प्राप्त	1.97 करोड़
युद्ध विधवा	1.84 करोड़
शारीरिक विकलांग	135.71 करोड़
कैंसर पीड़ित	2.13 करोड़
थेलेसीमिया रोगी	38 लाख
पुरस्कार प्राप्त शिक्षक	4 लाख
एचआरटीसी विधवाएं	1.07 करोड़
सचिवालय सुरक्षाकर्मी	6 लाख
महिलाओं को रक्षा बंधन व भैया दूज पर	66 लाख
महिलाओं को ईद पर	14 लाख
कुष्ठ रोगी	35 लाख
लोक सेवा आयोग व कर्मचारी आयोग	14 लाख
केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र	1.46 करोड़
केंद्रीय विद्यालय छात्र	1.11 करोड़
महिलाएं	20.67 करोड़
दिव्यांगजन	12.69 करोड़
विधायक व सांसद	49 लाख
कुल योग	433.83 करोड़

एचआरटीसी की बस ● जागरण आर्काइव

27 श्रेणियों को छूट देकर सामाजिक दायित्व हो रहा पूरा

433.83 करोड़ रुपये रियायतों पर वार्षिक खर्च कर रहा है परिवहन निगम

1400 करोड़ रुपये के घाटे में पहुंच चुका है निगम, वेतन देने में भी परेशानी

307 करोड़ रुपये का बजट मिला है इस वर्ष में प्रदेश सरकार से परिवहन निगम को

परिवहन निगम सामाजिक दायित्व निभा रहा है। निगम को वित्तीय संकट से उबारने और सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रदेश सरकार को रियायतों पर होने वाला खर्च एकमुश्त देना चाहिए।

-मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री।

कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर हनोगी की तरह अन्य सुरंगों में भी होगी रोशनी की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, मंडी : कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर हनोगी की तरह सभी सुरंगों में रोशनी की व्यवस्था होगी। इससे वाहन चालकों को कोई असुविधा नहीं होगी। हनोगी सुरंग में रोशनी (लाइट्स) का ट्रायल देखने के बाद सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को सभी सुरंगों में ऐसी ही रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सभी सुरंगों का निर्माण अलग-अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है। डिजाइन व रोशनी की व्यवस्था भी अलग-अलग है। कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नाममात्र लाइट ही लगा रखी हैं।

हनोगी में लगी लाइट्स सुरंग को चार चांद लगा रही हैं। मंत्रालय उद्घाटन से पहले हर चीज को बारीकी से जांच रहा है, ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। कैंचीमोड़ से भवाना के बीच बनी पांच सुरंगों के बाहर की गई पेंटिंग की लोग सराहना कर रहे हैं। इसको लेकर भी मंत्रालय ने कुछ आपत्ति जताते हुए बदलाव के निर्देश दिए हैं। हालांकि पेंटिंग टेंडर का हिस्सा नहीं है।

कंस्ट्रक्शन कंपनी ने देवभूमि को देखते हुए सुरंगों के बाहर भगवान शिव व कई अन्य देवी-देवताओं की पेंटिंग बनाई हैं। कीरतपुर से नागचला, पंडोह से टकोली व टकोली से कुल्लू के बीच फोरलेन पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका। 10 सुरंगें वाहनों के लिए खोल दी हैं। कई दिन से ट्रायल चल रहा है। सामने आ रही कमियों को एनएचएआइ दूर करवा रहा है। फोरलेन का उद्घाटन अगले माह तय है। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय व प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। तैयारियों की समीक्षा को लेकर मंत्रालय ने एनएचएआइ के परियोजना निदेशक वरुण चारी को दिल्ली तलब किया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को उनकी बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मिलते ही उद्घाटन की तिथि पर भी मुहर लग जाएगी। यह फोरलेन प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पर्यटन को पंख लगने से लोगों की आर्थिक सुदृढ़ होगी। आवागमन भी पहले से अधिक सुगम होगा।

तैयारी

- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआइ को दिए निर्देश
- जल्द तय होगी उद्घाटन की तिथि, शुरू हुआ बैठकों का दौर
- सुरंगों के बाहर की गई पेंटिंग में भी किया जाएगा बदलाव

फोरलेन पर दूधिया रोशनी से जगमग हनोगी में बनी यातायात सुरंग ● सौजन्य : नार्दन फिल्म्स

उद्घाटन की तिथि के लिए मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। सुंरगों व मार्ग में जहां कमियां पाई गई हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। सुरंगों में रोशनी की उचित व्यवस्था की जा रही है, ताकि वाहन चालकों को कोई असुविधा न हो। -वरुण चारी, परियोजना निदेशक एनएचएआइ मंडी

भानुपल्ली-बैरी-लेह रेलमार्ग पर पटरी बिछाने का कार्य शुरू

पहाड़ों में बनने वाली भारतीय रेलवे की पहली ब्राडगेज लाइन

सुनील शर्मा ● बिलासपुर

7 सुरंग में जर्मन की ब्लास्टल्स तकनीक का किया जा रहा इस्तेमाल, मिलेंगी कई सुविधाएं

63 किलोमीटर लंबी रेललाइन पर भू अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा, अब आएगी काम में तेजी

भानुपल्ली-बैरी-लेह लद्दाख रेलमार्ग पर दशकों बाद पटरी बिछाने का कार्य शुरू हुआ है। पहाड़ों में बनने वाली भारतीय रेलवे की यह पहली ब्राडगेज लाइन होगी, जिसे जर्मन तकनीक की मदद से तैयार किया जा रहा है। प्रथम चरण में पंजाब व हिमाचल के 20 किलोमीटर के हिस्से की सात सुरंग में जर्मन की ब्लास्टल्स तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब के भानुपल्ली से हिमाचल के बैरी तक 63 किलोमीटर लंबी रेललाइन पर भू अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस रेललाइन पर निर्मित होने वाली 20 सुरंग में से आठ तैयार हो चुकी हैं और अब इनमें पटरी बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। सुरंगों में पटरियां बिछाने के लिए ब्लास्टल्स स्लैब तैयार करने का लक्ष्य अगस्त तक रखा है। इसके बाद दूसरे चरण में पुलों व रेलवे स्टेशन पर पटरी बिछाने का कार्य किया जाएगा। रेलवे स्टेशन भानुपल्ली का निर्माण कार्य भी जारी है।

रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि रेललाइन व सुरंगों के निर्माण का कुछ कार्य मैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर रही है। कंपनी ने सुरंगों के अंदर रेललाइन निर्माण के लिए भारतीय पीपी मंडल कंपनी को टेंडर दिया है। यह कंपनी सुरंगों के अंदर 3.5 किलोमीटर पर पटरी के लिए ब्लास्टल्स स्लैब बिछाने का कार्य शुरू कर चुकी है।

पंजाब में ब्लास्टल्स तकनीक से तैयार किए जा रेल पटरी के स्लैब ● जागरण

आठ सुरंग तैयार

पंजाब व हिमाचल के बीच बन रही रेल परियोजना की 20 में से 16 सुरंग का निर्माण कार्य जारी है। आठ सुरंग तैयार हो चुकी हैं और बाकी का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। रेलमार्ग पर 26 पुल बनाए जा रहे हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है। सात रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला रेलवे स्टेशन भानुपल्ली होगा। थालु, पहाड़पुर, धरोट, जगातखाना, बिलासपुर व बरमाणा में स्टेशन होंगे।

क्या है जर्मन तकनीक

देश को लेह लद्दाख से जोड़ने व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस रेललाइन को आधुनिक बनाया जा रहा है। यही कारण है कि सुरंगों के अंदर जर्मन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में अब तक पटरियों के बीच रोड़ी व लोहे के एंगल डालकर उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है लेकिन जर्मन तकनीक से अब कंक्रीट का स्लैब बनाया जाएगा, जो रेलगाड़ी की गति के लिए भी कारगर होती है।

पीजीआइ सेटेलाइट सेंटर ऊना के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में पीजीआइ के सेटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। 495 करोड़ रुपये के खर्च से 300 बेड का यह सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में मरीजों के लिए ओपीडी से लेकर सर्जरी व आपरेशन के अलावा आइसीयू से जुड़ी सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। पीजीआइ के उपनिदेशक कुमार गौरव धवन ने बताया अब सैद्धांतिक रूप से एनवायरमेंट क्लीयरेंस मिल गई है। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन स्टेट एनवायरमेंट इंपेक्ट असेसमेंट अथारिटी (एसईआइएए) ने एनवायरमेंट क्लीयरेंस दी है। इसकी सूचना पीजीआइ की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड है। अक्टूबर, 2023 तक सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

सेंटर में ओपीडी, आपरेशन थिएटर, सर्जरी रूम के अलावा अन्य विभाग के लिए मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कमरे और लैब होंगी। आइसीयू और हाई डिपेंडेंसी बेड वार्ड के अलावा कई नई तकनीक से लैस स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रदेश से संबंधित खबरें www.jagran.com पर पढ़ें

- अक्टूबर तक निर्माण शुरू हो जाएगा 495 करोड़ रुपये आएगी लागत
- सेंटर में ओपीडी, ओटी, सर्जरी रूम के अलावा सुविधाएं होंगी

संगरूर सेटेलाइट सेंटर बनकर तैयार

पंजाब के संगरूर पीजीआइ सेटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस सेंटर का उद्घाटन अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। सेंटर पर 449 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सेंटर में मरीजों के लिए ओपीडी सेवा भी शुरू की जा चुकी है। सेंटर के लिए प्रथम चरण में 341 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसमें डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड अटेंडेंट और अन्य पदों पर भर्ती की जा रही है। पंजाब के फिरोजपुर में भी सेटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

वर्ष 2025 तक तीनों सेटेलाइट सेंटर पूरी तरह संचालित होंगे

कुमार गौरव धवन ने बताया स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जिस एजेंसी को पीजीआइ के इन तीनों सेटेलाइट सेंटर के निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। एजेंसी को वर्ष 2025 के शुरुआत तक इन तीनों सेटेलाइट सेंटर को पूरी तरह संचालित करने के लिए लक्ष्य दिया गया है।

हाई कोर्ट से कुपवी कालेज में शिक्षकों के पद भरने का आदेश

विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चौपाल उपमंडल के डिग्री कालेज कुपवी में शिक्षकों के रिक्त पद भरने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंदर सिंह की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि शहर के कालेजों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार शहर के उन शिक्षकों को प्रदेश के दूरदराज के संस्थानों में तैनाती दे सकती है, जिन्होंने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है। अदालत ने सरकार की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि कुपवी के डिग्री कालेज में शिक्षकों के आठ पद स्वीकृत किए गए हैं, जोकि सभी खाली हैं। इसी तरह गैर शिक्षकों के 10 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से केवल चपरासी के तीन और चौकीदार के दो पद भरे गए हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर अदालत ने संज्ञान लिया है। खबर में प्रकाशित किया गया था कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवंबर 2021 में घोषणा की थी कि इस दूरदराज के उपविभाजन में एक कालेज खोला जाएगा। पहले बैच को जुलाई 2022 में भर्ती कराया गया था। हालांकि, कालेज में पांच चपरासी और एक क्लर्क है, लेकिन कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया है।

कालेज के पीटीए संघ ने दो निजी शिक्षकों को काम पर रखा है। कुपवी कालेज के पास अपनी खुद की इमारत भी नहीं है।

चार तहसीलदार पदोन्नत एसडीएम लगाए

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश कार्मिक विभाग ने चार तहसीलदारों को पदोन्नत कर एचएएस अधिकारी बनाया है। जोगिंद्र पटियाल को पदोन्नति के बाद एसडीएम चुराह, संजीव कुमार को एसी टू डीसी किन्नौर, बचित्र सिंह को एसडीएम थुनाग और अमन कुमार को एसडीएम कुपवी लगाया गया है। जबकि राजेंद्र गौतम को एसडीएम धर्मपुर (मंडी) लगाया गया है।

उत्तर पुस्तिका गुम होने पर दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं : कोर्ट

जागरण संवाददाता शिमला : उत्तर पुस्तिका गुम होने पर अब दोबारा से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला के आर्डिनेंस 6.67 को अनुचित ठहराते हुए खारिज कर दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंदर सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उत्तर पुस्तिका गुम होने की स्थिति में विद्यार्थी को आनुपातिक भागफल के हिसाब से नंबर दिए जाना उचित है। इस हिसाब से विद्यार्थी को अन्य विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात लगाकर गुम हुई उत्तर पुस्तिका वाले विषय में नंबर दिए जाते हैं। कोर्ट ने बीएड के प्रशिक्षु नेहर सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तिका गुम होने की स्थिति में उस विषय की दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य करता है। इस बाध्यता को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्यार्थी पहले ही उक्त परीक्षा दे चुका होता है और उत्तर पुस्तिका गुम होने में उसकी कोई गलती नहीं होती। मामले के अनुसार प्रार्थी ने अगस्त 2022 में बीएड के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दीन दयाल महेश पब्लिक कालेज आफ एजुकेशन सुघ भटौली जिला कांगड़ा के छात्र के तौर पर दी थी। 22 अगस्त, 2022 को विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित किया, परंतु एक विषय में प्रार्थी का परिणाम आरएलए (रिजल्ट लेट डियू टू अवार्ड) बताया गया।

प्रार्थी के छानबीन करने पर बताया गया कि उसकी उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय ने प्राप्त नहीं की गई है। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि उसके संस्थान ने उत्तर पुस्तिका भेजी ही नहीं। विश्वविद्यालय और संस्थान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इस कारण प्रार्थी को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। विश्वविद्यालय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आर्डिनेंस 6.67 के अनुसार ऐसी परिस्थिति में केवल प्रार्थी को फिर से परीक्षा देने का अवसर दिया जा सकता है।

- एचपीयू के आर्डिनेंस 6.67 को अनुचित ठहराते हुए खारिज किया
- कहा-अन्य विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात लगाकर नंबर देना उचित

एग्जीक्यूविट इंजीनियर को तीन जिले पार दिया अतिरिक्त कार्यभार

राज्य ब्यूरो, शिमला : लोक निर्माण विभाग में एक इंजीनियर को तीन जिले पार कर अतिरिक्त दायित्व देने का मामला सामने आया है। बिलासपुर जिला के घुमारवीं मंडल में नियुक्त एग्जीक्यूविट इंजीनियर मनीष सहगल को कांगड़ा जिला के भवारना मंडल का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है।

हैरानी यह कि विभाग को कांगड़ा जिला में कोई भी ऐसा एग्जीक्यूविट इंजीनियर नहीं मिला, जिसे भवारना मंडल का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा जा सके। लोक निर्माण विभाग ने 19 मई को सहगल का तबादला भवारना से घुमारवीं मंडल किया था। अब सोमवार को सहगल को भवारना का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है।

इस संबंध में विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता का कहना था कि भवारना मंडल में आडिट नहीं हुआ है। इस मंडल में आडिट टीम आने वाली है, जिसे देखते हुए सहगल को केवल दो-तीन सप्ताह के लिए भवारना का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। क्योंकि सहगल घुमारवीं से पहले भवारना मंडल में नियुक्त थे। उन्हें उस मंडल की हर प्रशासनिक जानकारी है जोकि ऑडिट टीम को उपलब्ध करवाई जानी है।

नादौन में सीनियर वर्ग की राज्यस्तरीय क्रिकेट स्पर्धा के दौरान विवाद, नहीं हुआ मैच

संवाद सहयोगी, नादौन : अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम अमतर (नादौन) में सोमवार को सीनियर वर्ग की राज्यस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान विवाद हो गया। ऊना व कांगड़ा की टीम के बीच मैच खेला जाना था। कांगड़ा के खिलाड़ियों का मैच खेलने वाली टीम पर अपनी ही क्रिकेट एसोसिएशन के साथ विवाद हो गया। इस कारण सुबह दोनों टीमों के बीच टास नहीं हुआ।

ऊना की टीम काफी समय तक मैच शुरू होने का इंतजार करती रही लेकिन कांगड़ा की टीम मैदान में नहीं आई। अंपायर ने कांगड़ा की टीम को स्थिति स्पष्ट करने को कहा तो कप्तान ने लिखित में मैच खेलने से मना कर दिया। क्रिकेट के नियमों के तहत ऊना को विजेता घोषित कर दिया। क्रिकेट एसोसिएशन हमीरपुर के अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने बताया कि कांगड़ा टीम के कप्तान ने लिखित में मैच न खेलने के बारे में सूचना दी थी। मैच न होने से ऊना को विजेता घोषित किया गया।

कांगड़ा की टीम प्रतियोगिता से बाहर : विवाद के कारण कांगड़ा की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। कांगड़ा ने तीन मैच खेले थे। सोमवार को कांगड़ा का क्वार्टर फाइनल मैच ऊना के साथ होना था लेकिन मैच नहीं हुआ। ऊना सेमीफाइनल में पहुंच गया है।

कांगड़ा जिला टीम के कप्तान ने खेलने से किया इन्कार, ऊना की टीम विजेता घोषित, सेमीफाइनल में पहुंची टीम

टीम का आपसी विवाद है। निर्णय लेने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इसमें असीम अग्रवाल को संयोजक, नागेश्वर मनकोटिया व अशोक शर्मा सदस्य बनाए गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि क्या विवाद था। टीम के प्रतियोगिता से बाहर होने पर नुकसान हुआ है।

-विजय शर्मा, अध्यक्ष, जिला क्रिकेट एसोसिएशन कांगड़ा।

फूड सप्लीमेंट की आड़ में नकली दवाओं का उत्पादन

मूपेंद्र ठाकुर ● सोलन

दवा या धोखा

- न तो दवा नियंत्रक व न ही खाद्य सुरक्षा विभाग कर सकता है न्यूट्रासिटीकल कंपनियों की जांच
- नकली दवा उत्पादन में संलिप्त पाई गईं पांच में से तीन कंपनियां फूड सप्लीमेंट बनाने वाली

हिमाचल प्रदेश में न्यूट्रासिटीकल (फूड सप्लीमेंट बनाने वाली) कंपनियों की आड़ में नकली दवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। अब तक नकली दवा उत्पादन में संलिप्त पाई गईं पांच में से तीन कंपनियां फूड सप्लीमेंट बनाने वाली हैं। सोलन जिला के बद्दी स्थित इन कंपनियों के पास फूड लाइसेंस था। नियम के तहत ये एलोपैथी दवाओं का उत्पादन भी नहीं कर सकती हैं। इनकी जांच का जिम्मा न तो दवा नियंत्रक के पास है और न ही प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग इनके सैंपल भर सकता है। सरकारी तालमेल की कमी का लाभ कुछ न्यूट्रासिटीकल कंपनियां उठा रही हैं।

प्रदेश में 100 से अधिक न्यूट्रासिटीकल कंपनियां हैं, जो मल्टीविटामिन टेबलेट और सिरप आदि का उत्पादन कर रही हैं। ये सभी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आती हैं। इन्हें लाइसेंस देने और जांच का दायित्व केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग के पास है। हिमाचल में केंद्रीय एजेंसी की पकड़ न के बराबर है। वर्ष में मुश्किल से एक या दो बार ही केंद्रीय एजेंसी इनकी जांच कर पाती है। सैंपल तो केवल उसी कंपनी से लिए जाते हैं, जिसकी शिकायत आई हो।

वर्ष 2006 तक फूड एंड प्रिवेंशन एक्ट के दायरे में सभी न्यूट्रासिटीकल कंपनियां आती थीं और इनकी जांच, सैंपलिंग और लाइसेंस जारी करने का दायित्व राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभाग के पास था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू हो गया। इसके तहत ये सारी शक्तियां केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग के पास चली गईं। प्रदेश में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारी न तो इन कंपनियों से सैंपल ले सकते हैं और न ही जांच कर सकते हैं। यही वजह है कि हिमाचल में न्यूट्रासिटीकल कंपनियों की आड़ में नकली दवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि जब यहां नकली दवाओं का उत्पादन हो रहा था तो इसका पता केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग को क्यों नहीं लगा। यदि इनकी नियमित जांच व सैंपलिंग होती तो देश के लाखों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में नहीं पड़ता।

-विभाग के पास प्रदेश में किसी भी न्यूट्रासिटीकल कंपनी से सैंपल लेने का अधिकार नहीं है और न ही इनकी जांच कर सकते हैं। यह अधिकार केवल केंद्रीय एजेंसी के पास है। हमें तो यह भी पता नहीं है कि प्रदेश में कितनी न्यूट्रासिटीकल कंपनियां मल्टीविटामिन टेबलेट व सिरप बना रही हैं।

-डा. विजया, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग शिमला।

अब तक तीन ऐसी कंपनियों का पता चला है, जिनके पास फूड लाइसेंस था। ग्लेनमार्स, आर्या और एक्लाइन कंपनियां नकली दवाओं का उत्पादन कर रही थीं। हम केवल सूचना के आधार पर ही न्यूट्रासिटीकल कंपनियों में दबिश दे सकते हैं, नियमित जांच का अधिकार हमारे पास नहीं है।

-नवनीत मरवाह, राज्य दवा नियंत्रक।

प्रदेश के 2504 गांवों में बीएसएनएल शुरू करेगा 4जी मोबाइल फोन सेवा

जागरण संवाददाता, मंडी : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) प्रदेश के 2504 गांवों को 4जी कनेक्टिवटी देने जा रहा है। इसके लिए 631 नए टावर लगेंगे। बीएसएनएल के पहले हुए सर्वे के आधार पर इन गांवों को जोड़ा जाएगा। गांवों में आप्टिकल फाइबर लगाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी और उनको 50 प्रतिशत कमीशन दी जाएगी।प्रदेश परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक जेएस सहोता ने मंडी में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जिला मंडी के 238 गांवों के लिए 74 और कुल्लू के 387 गांवों के लिए 62 नए टावर लगेंगे। इसी तरह 4जी सेजुरेशन प्रोजेक्ट के तहत धर्मशाला में 119, हमीरपुर में 62, शिमला में 199, सोलन में 115 टावर लगेंगे। इस अवसर पर महा प्रबंधक, दूरसंचार मंडी क्षेत्र हरीश चंद भी उपस्थित थे।

शुद्धिपत्र

मैसर्स फ्रेंको लियोन लिमिटेड (परिसमापन में)

(सीआईएन: U74899DL1995PLC074764)

परिसमापक: अनिल कोहली (पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00112/2017-2018/10219)

पत्राचार का पता: 409, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

ईमेल: insolvency@arck.in, सम्पर्क नं. 011-40078344

फ्रेंको लियोन लिमिटेड के मामले में **दिनांक 20.05.2023 को प्रकाशित ई-नीलामी नोटिस और दिनांक 22.05.2023 को प्रकाशित शुद्धिपत्र** के संदर्भ में, कृपया ध्यान दें कि उक्त ई-नीलामी को माननीय एनसीएलएटी के दिनांक 26.05.2023 के आदेश द्वारा पारित निर्देशों के अनुसरण में अगले नोटिस तक रोक कर रखा गया है।

अनिल कोहली
परिसमापक – फ्रेंको लियोन लिमिटेड

दिनांक 30.05.2023
स्थान: नई दिल्ली

रजि. नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P00112/2017-2018/10219
एएफए वैध: 28.03.2024 तक

Postgraduate Institute of Child Health

Sector-30, Noida-201303,Gautam Budh Nagar, U.P. (India)

website - www.ssphpgti.ac.in, Email Id: facultyrecpgich@gmail.com

Advertisement No.-PGICH,NOIDA/Exec.Reg./2023/08 Dated: 29/05 /2023

ENGAGEMENT OF RETIRED FACULTY AS PROFESSOR (CONSULTANT) ON CONTRACT BASIS

Applications are invited for the following positions-

Professor (Consultant) – 01 post each, in the departments of Paediatric Cardiology, Paediatric Neurology, Paediatric Urology, Paediatric Surgery, Paediatric Haematology-Oncology, Biochemistry and Microbiology.

1. The posts are contractual and open only to the retired professors of the medical colleges/institutes. **2.** Short listed candidates shall be called for the Interview in the office of the Director, PGICH, Noida, U.P. **3.** Please visit our website **www.ssphpgti.ac.in** for details and application form.

Last date for submission of soft copy of application : 13.06.2023

Director

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
HINDUSTAN COPPER LIMITED
www.hindustancopper.com

चिकित्सकों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू (चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ)

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), परिशोधित तांबे के खनन और उत्पादन में नियोजित उर्ध्वाधर एकीकृत बहु-इकाई अनुसूची 'ए' मिनीरत्न सीपीएसई को निम्नानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में सहायक चिकित्सा अधीक्षक (ई-2) और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ई-1) के पद के लिए योग्यताप्राप्त आवेदकों की आवश्यकता है।

ग्रेड	वेतनमान (रु.) (01/01/2017 से प्रभावी)	योग्यता	उम्र-सीमा (वर्ष) (अधिकतम)	अनुभव (वर्ष)	रिक्तियों की सं.
ई-2	50000-160000	एमबीबीएस	35	3	5 (अजा: 1, अपिव: 1, अना: 3)
		एमबीबीएस के साथ पीजी डिप्लोमा	40	2	
		एमबीबीएस के साथ पीजी डिग्री	40	शून्य	
ई-1	40000-140000	एमबीबीएस	32	शून्य	5 (अजा: 1, अपिव: 1, अना: 3)
		एमबीबीएस के साथ पीजी डिप्लोमा	35	शून्य	

टिप्पणी:

- स्पेशलिस्ट: जनरल सर्जन/ऑर्थो सर्जन/जनरल फिजिशन/कार्डियोलॉजिस्ट/पेडियाट्रिक्स/ईएनटी स्पेशलिस्ट/ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट/गाइनीकोलॉजिस्ट।
- यदि ई-2 ग्रेड में स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं है तो पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) को रु.40000-140000 के वेतनमान में ई-1 ग्रेड में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए विवेचित किया जाएगा।

वॉक-इन इंटरव्यू का आयोजन 24.06.2023, 28.06.2023 और 01.07.2023 को क्रमशः रायपुर, राँची और जयपुर में किया जाएगा।

इच्छुक आवेदक पद, पात्रता मानदंड, रिपोर्टिंग समय, आवेदन फॉर्म आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए एचसीएल की वेबसाइट अर्थात **www.hindustancopper.com** के कैरियर पेज को देख सकते हैं।

Regd. Office : Tamra Bhavan, 1, Ashutosh Chowdhury Avenue, Kolkata – 700 019, Tel: 033 2283 2226, E-mail: careers@hindustancopper.com, CIN : L27201WB1967GOI028825